नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 094
दि. 05.01.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा


# 2026 की सियासी जंग का शंखनाद: अमित शाह का बड़ा दावा, तमिलनाडु में बनेगी एनडीए सरकार, डीएमके पर भ्रष्टाचार और वंशवाद का हमला

**(जीएनएस)**। पुदुक्कोट्टई/नई दिल्ली। तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक आक्रामक और स्पष्ट बयान ने राज्य की सियासत को नई धार दे दी है। रविवार को पुदुक्कोट्टई में आयोजित 'तमिलगम थलाई निमिरा तमिलिन पायनम' यात्रा के समापन समारोह में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने न केवल 2026 के चुनावी परिणाम को लेकर बड़ा दावा किया, बल्कि सत्तारूढ़ डीएमके सरकार और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर सीधा और तीखा हमला भी बोला। शाह ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी और राज्य की जनता इस बार विकास, सुशासन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निर्णायक फैसला करेगी। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि तमिलनाडु की जनता लंबे समय से ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो केवल भाषण नहीं, बल्कि जमीन पर काम करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कई राज्यों ने अभूतपूर्व विकास देखा है और अब समय आ गया है कि तमिलनाडु भी उस विकास यात्रा का हिस्सा बने। शाह ने लोगों से अपील की कि वे केंद्र सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को देखें और यह तय करें कि राज्य को किस दिशा में आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि एनडीए विकास, पारदर्शिता और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक है, जबकि डीएमके की राजनीति केवल आरोप-प्रत्यारोप, परिवारवाद और सत्ता के दुरुपयोग तक सीमित रह गई है।

गृह मंत्री ने डीएमके सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले वर्षों में तमिलनाडु की जनता को केवल निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है और आम आदमी की समस्याओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। शाह ने कहा कि डीएमके ने चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को भूल गई। उन्होंने कहा कि सड़कें बदहाल हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, शिक्षा व्यवस्था दिशाहीन हो चुकी है और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों पर भी सरकार जनता को राहत देने में असफल रही है। शाह ने दावा किया कि राज्य के लोग अब समझ चुके हैं कि यह सरकार केवल सत्ता में बने रहने के लिए काम कर रही है, न कि जनता के हित के लिए।

अमित शाह ने अपने भाषण में वंशवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और डीएमके पर परिवार केंद्रित राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति को कुछ लोगों ने अपनी निजी जागीर बना लिया है। पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी, यह साफ दर्शाता है कि डीएमके का लक्ष्य लोकतंत्र को मजबूत करना नहीं, बल्कि सत्ता को एक ही परिवार में सीमित रखना है। शाह ने मुख्यमंत्री स्टालिन को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि तमिलनाडु की जनता अब इस राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी और 2026 में वंशवाद का अंत तय है। उन्होंने कहा कि राज्य को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो मेहनत और योग्यता के आधार पर आगे आए, न कि केवल अपने उपनाम के बल पर।

भाषा और संस्कृति के सवाल पर भी अमित शाह ने डीएमके के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डीएमके बार-बार यह भ्रम फैलाने की कोशिश करती है कि भाजपा या एनडीए तमिल भाषा और संस्कृति के खिलाफ है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल भाषा और साहित्य को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आईएएस और आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं को तमिल भाषा में आयोजित करने की सुविधा, महान कवि सुब्रमण्यम भारती के नाम पर चेयर की स्थापना और तिरुक्कुरल जैसे महान ग्रंथ का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद, यह सब इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार तमिल विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने डीएमके सरकार पर यह गंभीर आरोप भी लगाया कि राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं का सम्मान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और हिंदू परंपराओं का बार-बार अपमान किया गया और धार्मिक गतिविधियों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाए गए। शाह ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमिपूजन के समय तमिलनाडु में कथित तौर पर लगाए गए अघोषित कर्फ्यू और धार्मिक आयोजनों पर रोक का जिक्र करते हुए कहा कि यह न केवल आस्था का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार धर्म, संस्कृति और परंपरा का सम्मान करती है और सभी समुदायों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है।

अपने संबोधन के अंत में अमित शाह ने तमिलनाडु की जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि 2026 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य को नई दिशा देने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि जनता को यह तय करना है कि क्या वह भ्रष्टाचार, वंशवाद और विफल नीतियों वाली सरकार को फिर से मौका देगी या विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व को चुनेगी। शाह ने विश्वास जताया कि भाजपा और एआईएडीएमके का गठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा और तमिलनाडु में एक स्थिर, ईमानदार और विकासोन्मुख सरकार का गठन करेगा। उन्होंने कहा कि 2026 का चुनाव तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा और राज्य एक नए युग में प्रवेश करेगा।

## बांग्लादेश में कट्टरता की दोहरी सूरत पर तसलीमा नसरीन की सख्त चेतावनी, भारत-विरोधी एजेंडे को बताया असली खतरा

**(जीएनएस)**। ढाका/नई दिल्ली। निर्वासित और बेबाक लेखिका तसलीमा नसरीन ने एक बार फिर बांग्लादेश की मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कट्टरपंथ और जिहादी मानसिकता के बढ़ते प्रभाव को उजागर किया है। अपने हालिया बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिहाद अब दो अलग-अलग चेहरों के साथ सामने आ रहा है, जो देखने में भले ही भिन्न हों, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है और वह है भारत का विरोध करना। तसलीमा नसरीन के मुताबिक यह खतरा केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव भारत-बांग्लादेश संबंधों और पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर पड़ सकते हैं। तसलीमा नसरीन ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश में एक वर्ग वह है जो पारंपरिक धार्मिक पहचान के साथ सामने आता है, दाढ़ी-टोपी पहनता है, मदरसों से निकलता है और खुले तौर पर कट्टर जिहादी सोच को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो देखने में आधुनिक लगता है, पश्चिमी कपड़े पहनता है, विश्वविद्यालयों से डिग्रियां लेकर निकलता है और खुद को प्रगतिशील या शिक्षित वर्ग के रूप में पेश करता है। लेकिन

नसरीन के अनुसार, इन दोनों वर्गों की सोच और लक्ष्य में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। दोनों ही भारत-विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े होकर हिंसा और नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बांग्लादेश का पूरा समाज अभी जिहादी नहीं बना है और यह बात बेहद अहम है। तसलीमा नसरीन ने कहा कि देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। यही वर्ग बांग्लादेश के भविष्य के लिए उम्मीद की किरण है। उनका मानना है कि अगर इन आवाज़ों को दबा दिया गया या उन्हें अलग-थलग कर दिया गया, तो कट्टरपंथी ताकतों को देश पर पूरी तरह हावी होने का मौका मिल जाएगा।

तसलीमा नसरीन ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध कमजोर होते हैं, तो इसका सीधा फायदा कट्टरपंथियों को मिलेगा। उनका कहना है कि लोगों के बीच संपर्क टूटना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कम होना और आपसी संवाद का अभाव, जिहादी विचारधारा को फैलने का खुला मैदान दे देता है। नसरीन ने कहा कि नफरत का जवाब नफरत से देना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे हालात और बिगड़ते हैं। मौजूदा समय में शांति, संवाद और सह-अस्तित्व ही एकमात्र रास्ता है, जिससे दोनों देशों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है।

अपने बयान में तसलीमा नसरीन ने खेल, कला और संस्कृति को राजनीति से दूर रखने की भी जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि क्रिकेट, सिनेमा, संगीत, फैशन, साहित्य और पुस्तक मेले जैसी गतिविधियां लोगों को जोड़ने का काम करती हैं और इन्हें किसी भी हाल में बंद नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर राजनीतिक तनाव के चलते इन पर रोक लगाई जाती है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश को ही होगा, क्योंकि इससे समाज और ज्यादा बंद और कट्टर होता जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्कृति और रचनात्मकता ही वह माध्यम हैं, जिनके जरिए समाज में सहिष्णुता और आपसी समझ को बचाया जा सकता है।

तसलीमा नसरीन ने दो टूक शब्दों में कहा कि बांग्लादेश के पास अभी भी एक विकल्प मौजूद है। यदि देश सह-अस्तित्व, संवाद और सांस्कृतिक खुलेपन को बचाए रखता है, तो वह एक आधुनिक, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राष्ट्र बन सकता है। लेकिन अगर कट्टरता को लगातार नजरअंदाज किया गया और उसे बढ़ने दिया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब यह सोच पूरे समाज को जकड़ लेगी। उनके अनुसार, यह सिर्फ बांग्लादेश की समस्या नहीं होगी, बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर पड़ेगा, और भारत को भी इसके परिणामों के लिए तैयार रहना होगा।

## वैश्विक ताकत बनाम अंतरराष्ट्रीय कानून: वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई पर शशि थरूर का तीखा प्रहार, विश्व व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली। वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की कथित सैन्य कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तीखी बहस छेड़ दी है। कांग्रेस सांसद और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने इस मुद्दे पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की खुली अवहेलना है। थरूर ने मौजूदा वैश्विक हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि आज की दुनिया में "जिसकी लाठी, उसकी भैंस" का सिद्धांत हावी होता जा रहा है, जहां ताकतवर देश नियमों और कानूनों को नजरअंदाज कर अपने हित साध रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियाद नियमों, संधियों और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों पर टिकी है। अगर कोई देश यह मानने लगे कि वह अपनी सैन्य शक्ति के बल पर किसी दूसरे देश में घुसकर वहां की सरकार या राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, तो यह पूरी वैश्विक प्रणाली के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी देश, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, किसी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्र में इस तरह हस्तक्षेप

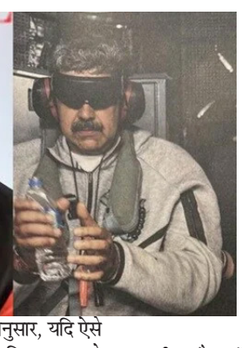

नहीं कर सकता। थरूर के अनुसार, यदि ऐसे कदमों को आज नजरअंदाज किया गया, तो भविष्य में यह अराजकता और अस्थिरता को जन्म देगा। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को गहरा झटका लगता है। उन्होंने आगाह किया कि अगर वैश्विक समुदाय ने समय रहते आवाज नहीं उठाई, तो आने वाले वर्षों में छोटे और कमजोर देशों की संप्रभुता सबसे ज्यादा खतरे में होगी। थरूर ने यह सवाल भी उठाया कि जब अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं पर है, वही अगर कमजोर पड़ जाएं, तो विश्व व्यवस्था कैसे टिक पाएगी।

इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार ने भी सतर्क रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा, भलाई और हितों को लेकर गंभीर है। मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और विवादों को सैन्य टकराव के बजाय बातचीत और शांतिपूर्ण माध्यमों से सुलझाने की अपील की है। भारत ने यह भी दोहराया कि किसी भी संकट का स्थायी समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव है, न कि बल प्रयोग से।

भारत सरकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए वेनेजुएला यात्रा को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। इसमें गैर-ज़रूरी यात्राओं से बचने और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे के कदम उठाने की बात भी कही गई है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने 3 जनवरी की रात वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की। इन रिपोर्टों में दावा किया गया है कि करीब 150 एयरक्राफ्ट के जरिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में बमबारी की गई। यही नहीं, कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के आवास में घुसकर उन्हें और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया और बाद में उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर मुकदमे चलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति स्पष्ट नहीं है और कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि क्या अंतरराष्ट्रीय कानून वास्तव में सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं, या फिर वैश्विक राजनीति में ताकत ही अंतिम फैसला करती है। शशि थरूर जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया यह संकेत देती है कि भारत जैसे देश इस तरह की कार्रवाइयों को केवल एक क्षेत्रीय घटना नहीं, बल्कि पूरी विश्व व्यवस्था के लिए चेतावनी के रूप में देख रहे हैं।

## असम में प्रियंका की तैनाती पर सियासी घमासान, दिलीप जायसवाल का कांग्रेस पर तीखा वार, बोले— अब वंशवाद नहीं, मेहनत से बनेगा नेतृत्व

**(जीएनएस)**। पटना। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रियंका गांधी को असम स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाए जाने के फैसले ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। इस फैसले पर बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जायसवाल ने कहा कि देश की जनता अब पहले जैसी भोली नहीं रही और "राजा का बेटा ही राजा बनेगा" वाली सोच को लोकतंत्र ने कब का खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज का भारत अवसरों का देश है, जहां एक आम कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है, बशर्ते संगठन उसे ईमानदारी और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ने का मौका दे। दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी ढांचे पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कांग्रेस के पास गांधी परिवार के अलावा कोई और नेतृत्व उभरकर सामने आने की क्षमता ही नहीं रखता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हर बड़े फैसले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम सामने आना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस अब भी वंशवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई है। जायसवाल ने भाजपा का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता भी मेहनत और संगठनात्मक क्षमता के बल पर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि पटना के एक 45 वर्षीय कार्यकर्ता को भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जैसे अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी है, जो यह दिखाता है कि पार्टी में प्रतिभा और समर्पण को महत्व दिया जाता है, न कि पारिवारिक पृष्ठभूमि को।

जायसवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस अगर सच में खुद को मजबूत करना चाहती है, तो उसे गांधी परिवार से बाहर निकलकर नए चेहरों को आगे लाना होगा। उन्होंने दावा किया कि लगातार चुनावी हार के बावजूद कांग्रेस ने कोई आत्ममंथन नहीं किया और वही पुरानी रणनीति दोहराई जा रही है। उनके अनुसार, असम जैसे महत्वपूर्ण राज्य में भी नेतृत्व की जिम्मेदारी किसी स्थानीय या जमीनी नेता को देने के बजाय फिर से परिवार के सदस्य को सौंपना कांग्रेस की सीमित सोच को दर्शाता है। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने असदुद्दीन ओवैसी के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। जायसवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से भारत ने अपनी सुरक्षा और सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है और यह साबित किया है कि देश अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने उसकी धरती पर मिसाइल परीक्षण कर यह संदेश दे दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जायसवाल ने कहा कि देश को लेकर किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बिहार की राजनीति से जुड़े सवालों पर बोलते हुए दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव के मामलों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने अदालत के सामने सभी सबूत रख दिए हैं और अब न्यायिक प्रक्रिया अपने अनुसार आगे बढ़ेगी। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और लालू यादव समेत सभी को संवैधानिक व्यवस्था और अदालत के आदेशों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए कानून के शासन में विश्वास रखते हैं और किसी के साथ राजनीतिक द्वेष के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाती।

## ड्यूटी निभाते हुए वीरगति: अनंतनाग में ऑक्सीजन की कमी से अमृतसर के सेना जवान प्रगट सिंह का निधन, घर-गांव में पसरा मातम

**(जीएनएस)**। अमृतसर/अनंतनाग। देश की रक्षा करते हुए एक और सपूत ने अपनी जान गंवा दी। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में ड्यूटी पर तैनात अमृतसर निवासी सेना जवान प्रगट सिंह की ऑक्सीजन की कमी और भीषण ठंड के कारण मौत हो गई। इस दुखद खबर के सामने आते ही उनके परिवार, गांव और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। जिस घर में कुछ दिन पहले तक हंसी-खुशी और गर्व का माहौल था, वहां अब सन्नाटा और आंसुओं का सैलाब है।

परिजनों के अनुसार, प्रगट सिंह भारतीय सेना की 19-11 बटालियन में तैनात थे और पिछले एक साल से अनंतनाग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे। करीब 15 वर्षों की सैन्य सेवा में उन्होंने देश के अलग-अलग संवेदनशील इलाकों में ड्यूटी निभाई, लेकिन कभी किसी गंभीर बीमारी की शिकायत नहीं हुई। परिवार का कहना है कि वे बीते 11 वर्षों से लगातार कठिन और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में तैनात रहे और हर बार ड्यूटी को प्राथमिकता दी। करीब डेढ़ महीने पहले ही वे छुट्टी पर घर आए थे और परिवार के साथ समय बिताकर फिर से कर्तव्य निभाने के लिए कश्मीर लौटे थे।

परिजनों ने बताया कि घटना से कुछ समय पहले प्रगट सिंह ने फोन पर बातचीत के दौरान चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि ड्यूटी पोस्ट पर ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है और वे इस समस्या को लेकर नीचे उतर रहे हैं। यह उनके और परिवार के बीच आखिरी बातचीत थी। इसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो सका और कुछ ही देर बाद सेना की ओर से उनके निधन की सूचना परिवार को दी गई। इस खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया।

जैसे ही जवान की मौत की सूचना गांव पहुंची, हर आंख नम हो गई। पड़ोसी, रिश्तेदार और गांव के लोग उनके घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाने लगे। हर कोई प्रगट सिंह की सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति को याद कर रहा है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि प्रगट सिंह पूरे इलाके के लिए गर्व का प्रतीक थे, जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा।

जवान की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। पति के असमय चले जाने से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रगट सिंह अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनका भविष्य अब परिवार की सबसे बड़ी चिंता बन गया है। बच्चों को पिता की शहादत पर गर्व तो है, लेकिन उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। परिवार का कहना है कि प्रगट सिंह हमेशा बच्चों को पढ़ा-लिखाकर अच्छा इंसान बनाना चाहते थे और देश सेवा का जज्बा उनमें भी देखना चाहते थे। इस घटना ने एक बार फिर कश्मीर जैसे दुर्गम और कठिन इलाकों में तैनात सैनिकों की चुनौतियों को सामने ला दिया है। भीषण ठंड, ऊंचाई, सीमित संसाधन और ऑक्सीजन की कमी जैसी परिस्थितियों में जवान अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। प्रगट सिंह की मौत सिर्फ एक परिवार की क्षति नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक गहरा नुकसान है।


नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

# छिन्न-भिन्न होती विश्व व्यवस्था, वैश्विक ढांचे के लिए संकट बन रहे नियमों की दुहाई देने वाले देश

संपादकीय

## ट्रंप की दादागीरी, वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाया

अमेरिकी सेनाओं द्वारा वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सहित जबरन उठा लाना केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी, अहंकार और एकतरफा विश्व दृष्टि की चरम अभिव्यक्ति है। यह घटना बताती है कि अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था ट्रंप के लिए महज शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल वे केवल तब करते हैं, जब उनसे उनका स्वार्थ सधता हो। एक स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति को इस तरह अपहृत करना उस दौर की याद दिलाता है, जब साम्राज्यवादी ताकतें कमजोर देशों पर खुली दादागीरी किया करती थीं। ट्रंप प्रशासन ने इस हमले को यह कहकर जायज ठहराने की कोशिश की कि वेनेजुएला से अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी और मादुरो की दमनकारी नीतियों के कारण वहां के लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसपैठ कर रहे थे। लेकिन यह तर्क सतही और सुविधाजनक बहाने से ज्यादा कुछ नहीं लगता। अमेरिका में नशीले पदार्थों की समस्या दशकों पुरानी है और यह किसी एक देश से जुड़ी नहीं है। मेक्सिको, कोलंबिया, अफगानिस्तान और यहां तक कि अमेरिका के भीतर भी ड्रग माफिया सक्रिय हैं। ऐसे में केवल वेनेजुएला को निशाना बनाना यह साबित करता है कि ट्रंप ने सच्चाई से ज्यादा अपनी राजनीतिक और भू-राजनीतिक सुविधा को प्राथमिकता दी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे गंभीर बात यह है कि ट्रंप ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किए। यह भी साबित नहीं किया गया कि वेनेजुएला के अपराधी गिरोह मादुरो की शह पर अमेरिका के खिलाफ किसी संगठित आतंकवादी गतिविधि में लिप्त थे। इसके उलट, निकोलस मादुरो ने स्वयं ट्रंप से बातचीत और संवाद का प्रस्ताव रखा था, ताकि आरोपों पर खुलकर चर्चा की जा सके। लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। यह रवैया बताता है कि उनका उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन था। असल में ट्रंप की नाराजगी की जड़ कहीं और है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है और लंबे समय से अमेरिकी तेल कंपनियों की नजर वहां के संसाधनों पर रही है। जब वेनेजुएला में वामपंथी रुझान वाले शासक सत्ता में आए और उन्होंने तेल व खनिज संसाधनों का राष्ट्रीयकरण शुरू किया, तब से अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध लगातार बिगड़ते चले गए। अमेरिकी कंपनियों को वहां से बाहर होना पड़ा और वाशिंगटन में यह संदेश गया कि वेनेजुएला उनके आर्थिक हितों को चुनौती दे रहा है। मादुरो से ट्रंप की खार इसलिए भी बढ़ी, क्योंकि वेनेजुएला ने रूस और चीन के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए। आज की वैश्विक राजनीति में रूस और चीन अमेरिका के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं। ट्रंप यह अच्छी तरह जानते हैं कि वे इन दोनों शक्तियों पर सीधे दबाव नहीं बना सकते। ऐसे में उन्होंने एक अपेक्षाकृत कमजोर देश को निशाना बनाना बेहतर समझा, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि जो अमेरिका की शर्तों पर नहीं चलेगा, उसका यही हश्र होगा। यह स्वीकार किया जा सकता है कि निकोलस मादुरो कोई आदर्श लोकतांत्रिक नेता नहीं हैं। उन पर चुनावों में धांधली, विपक्ष के दमन और तानाशाही शासन चलाने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया में वे अकेले ऐसे शासक हैं? यह सवाल ट्रंप की दोहरी नीति को उजागर करता है। ट्रंप ने दुनिया के कई तानाशाहों और मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन करने वाले शासकों के साथ दोस्ती निभाई है। सीरिया में सत्ता पर काबिज आतंकी सरगनाओं से लेकर खाड़ी देशों के निरंकुश शासकों तक, ट्रंप ने सभी को गले लगाया है, बशर्ते वे अमेरिका के हितों के अनुकूल हों। पाकिस्तान के प्रति ट्रंप का रवैया इस दोहरे मापदंड का सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान को वे एक महान देश बताते नहीं थकते, जबकि यह सर्वविदित है कि वहां की सेना और खुफिया एजेंसियां लंबे समय से आतंकी संगठनों को संरक्षण देती आई हैं। पाकिस्तान उन देशों में भी शामिल है, जहां से बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी होती है। इसके बावजूद ट्रंप ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ वैसी आक्रामक कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई, जैसी उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ दिखाई। इसका एक ही कारण है—पाकिस्तान अमेरिका की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करता है, जबकि वेनेजुएला उसकी नीतियों को चुनौती देता है।

दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का व्यवहार और भी अधिक बेलगाम होता जा रहा है। वे न केवल अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि दशकों से बनी वैश्विक सहमति और नियम आधारित व्यवस्था को भी ध्वस्त कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वेनेजुएला पर हमला और वहां के राष्ट्रपति का अपहरण इस बात का संकेत है कि ट्रंप अब किसी भी हद तक जा सकते हैं।

> अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर हो रही है, जहां शक्तिशाली देश नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वेनेजुएला और ईरान पर प्रतिबंधों से इसकी असमानता उजागर होती है। भारत एक संतुलनकारी भूमिका निभा रहा है, जो रणनीतिक स्वायत्तता और संवाद पर केंद्रित है। भारत ने नागरिक-केंद्रित विदेश नीति अपनाई है, मानवीय सहायता को प्राथमिकता दी है और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग की है, ताकि न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था बन सके।



आज अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। कई देश खुले तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं हो रहे। देश अब अपने हितों के लिए अकेले फैसले ले रहे हैं। दुनिया में युद्ध और हिंसा बढ़ गई है। जो देश नियम आधारित विश्व व्यवस्था की दुहाई देते थे आज वे ही वैश्विक व्यवस्था के लिए संकट बनते जा रहे हैं।

नियम आधारित विश्व व्यवस्था का मूल उद्देश्य संप्रभुता का सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन जैसी प्रमुख बातें थीं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं-संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, विश्व व्यापार संगठन और बहुपक्षीय संधियां इसी व्यवस्था का मजबूत स्तंभ थीं, परंतु आज स्थिति यह है कि नियमों का पालन केवल तब किया जाता है, जब वे शक्तिशाली देशों के हितों के अनुकूल हों।

जहां हित टकराते हैं, वहां नियमों की व्याख्या बदल जाती है या उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। वेनेजुएला और ईरान की घटनाएं दर्शाती हैं कि किस प्रकार आर्थिक प्रतिबंध तथा बाहरी शक्तियों का खुला हस्तक्षेप आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक घातक हथियार बन चुका है।

वेनेजुएला के मामले में आंतरिक राजनीतिक संकट और लोकतंत्र की दुहाई देते हुए बाहरी शक्तियों ने न केवल खुला राजनीतिक हस्तक्षेप किया है, बल्कि सत्ता परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की नीति भी अपनाई। सरकार की वैधता को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चुनौती दी गई, समानांतर सत्ता संरचनाओं को मान्यता दी गई और तेल, वित्तीय लेन-देन तथा विदेशी निवेश पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए।

इसी प्रकार ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून में समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ईरान एनपीटी का हस्ताक्षरकर्ता है और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) की निगरानी व्यवस्था को स्वीकार करता रहा है। इसके बावजूद उस पर लगाए गए एकतरफा और बहुपक्षीय प्रतिबंधों की तीव्रता यह दर्शाती है कि नियमों की व्याख्या राजनीतिक हितों के अनुसार की जाती है। इन प्रतिबंधों का प्रत्यक्ष प्रभाव वेनेजुएला तथा ईरान की पहले से कमजोर होती अर्थव्यवस्था पर पड़ा।

तेल निर्यात पर निर्भर देश की विदेशी मुद्रा आय में भारी गिरावट आई, मुद्रास्फीति बेकाबू हो गई और बुनियादी वस्तुओं की कमी हो गई। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं, कुपोषण बढ़ा और लाखों नागरिक बेहतर जीवन की तलाश में देश छोड़ने को विवश हुए। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था की मूल भावना-समानता, न्याय और संप्रभुता का सम्मान खोती जा रही है। विश्व तेजी से एक बहुध्रुवीय संरचना की ओर बढ़ रहा है, क्षेत्रीय शक्तियां अधिक मुखर हो रही हैं।

ऐसे समय में भारत एक संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है, जो रणनीतिक स्वायत्तता, संवाद और बहुपक्षीयता में विश्वास रखता है। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी विदेश नीति को नागरिक-केंद्रित और मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित किया है। वैश्विक संघर्षों और ध्रुवीकृत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बीच भारत ने किसी एक पक्ष में कठोरता से खड़े होने के बजाय संघर्षरत सभी पक्षों से संवाद बनाए रखने की नीति अपनाई है।

इस संतुलित दृष्टिकोण ने न केवल भारत को एक विश्वसनीय और उत्तरदायी वैश्विक भागीदार के रूप में स्थापित किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि विदेश नीति का अंतिम उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि मानव जीवन और गरिमा की रक्षा होना चाहिए। भारत ने संकटग्रस्त क्षेत्रों, आपदाग्रस्त देशों को मानवीय सहायता तथा खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मूलभूत विषयों को प्राथमिकता देकर यह स्पष्ट किया है कि भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर नागरिकों की आवश्यकताएं हैं।

इस दृष्टिकोण के माध्यम से भारत ने केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा ही नहीं की, बल्कि विकासशील देशों और वैश्विक दक्षिण की उन चिंताओं को भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुखरता से उठाया, जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की संरचनात्मक सीमाओं और प्रतिनिधित्व की कमी की ओर भी लगातार ध्यान आकर्षित किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग इस विश्वास पर आधारित है कि जब तक निर्णय-निर्माण प्रक्रियाएं अधिक समावेशी और न्यायसंगत नहीं होंगी, तब तक वैश्विक शांति और स्थिरता एक अधूरा लक्ष्य बनी रहेगी।

आज जब वैश्विक राजनीति टकराव, प्रतिबंधों और सैन्य शक्ति के इर्द-गिर्द सिमटती जा रही है, तब संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देना और संवाद को प्राथमिक साधन मानना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। नागरिकों की सुरक्षा, मानवीय गरिमा और विकासात्मक आवश्यकताओं को भू-राजनीतिक हितों से ऊपर रखना ही एक स्थायी और न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिला हो सकता है। भारत की विदेश नीति इसी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है-जहां शक्ति के बजाय विश्वास और प्रभुत्व के बजाय सहयोग को वैश्विक राजनीति का मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता है।

प्रेरणा

## धैर्य, साहस और विश्वास से रचा गया चिकित्सा का चमत्कार

मानव इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जो अपने कार्यों से केवल पेशे की सीमाओं में नहीं बंधते, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में डॉ. बेंजामिन कार्सन ऐसा ही एक नाम हैं, जिनकी जीवन यात्रा यह सिद्ध करती है कि असाधारण सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और अडिग विश्वास से जन्म लेती है। उनका जीवन और कार्य इस बात का प्रमाण हैं कि जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर विवेक से निर्णय लेता है, तब असंभव भी संभव बन जाता है।

डॉ. बेंजामिन कार्सन अमेरिका के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन हैं, लेकिन उनकी पहचान केवल एक कुशल सर्जन तक सीमित नहीं है। वे ऐसे चिकित्सक हैं, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान को मानवीय संवेदना, धैर्य और नैतिक साहस के साथ जोड़कर देखा। जिस दौर में वे अपने करियर के शिखर पर थे, उसी समय उनके सामने एक ऐसी चुनौती आई, जिसने पूरे चिकित्सा जगत को हिला कर रख दिया। उनके पास दो ऐसे शिशु लाए गए, जिनकी खोपड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई थीं। यह स्थिति चिकित्सा भाषा में "कंजॉइंड ट्विन्स" कहलाती है और जब जुड़ाव मस्तिष्क के स्तर पर हो, तो इसे सबसे जटिल और जोखिम भरा माना जाता है। इस तरह के मामलों में असफलता की आशंका अत्यंत अधिक होती है। कई बार ऐसे ऑपरेशन में एक या दोनों शिशुओं की जान चली जाती है। यही कारण था कि जब यह मामला सामने आया, तो अनेक वरिष्ठ डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने इसे लगभग असंभव करार दे दिया। कुछ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह जोखिम उठाना ही गलत है, क्योंकि सफलता की संभावना बहुत कम है। ऑपरेशन के दौरान जरा-सी चूक बच्चों के जीवन को समाप्त कर सकती थी। ऐसे में भय, संदेह और नकारात्मकता का वातावरण स्वाभाविक था। लेकिन डॉ. बेंजामिन कार्सन का दृष्टिकोण बाकी सबसे अलग था। उन्होंने इस चुनौती को केवल एक तकनीकी समस्या के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे मानव जीवन के प्रति अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा कि यदि सही योजना, धैर्य और टीमवर्क के साथ आगे बढ़ा जाए, तो इस असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनका यह आत्मविश्वास किसी अहंकार से नहीं, बल्कि गहन अनुभव, गहरी तैयारी और ईश्वर में अटूट विश्वास से उपजा था।

ऑपरेशन से पहले की तैयारी अपने आप में एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। डॉ. कार्सन ने अपनी टीम के साथ मिलकर हर संभावित स्थिति पर विचार किया। मस्तिष्क की संरचना, रक्त वाहिकाओं का जाल, तंत्रिकाओं की संवेदनशीलता—हर पहलू का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। यह तय किया गया कि किस क्षण क्या करना है, किस स्थिति में किस तरह का निर्णय लिया जाएगा। कई बार योजना बदली गई, दोबारा विश्लेषण हुआ और फिर उसे और अधिक सटीक बनाया गया। यह सब इसलिए किया गया, ताकि ऑपरेशन के दौरान घबराहट या जल्दबाजी की कोई गुंजाइश न रहे।

अंततः वह दिन आ ही गया, जब ऑपरेशन किया जाना था। ऑपरेशन थिएटर में असाधारण तनाव व्याप्त था। हर व्यक्ति जानता था कि यह केवल एक सर्जरी नहीं, बल्कि चिकित्सा इतिहास की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, समय मानो थम-सा गया। घड़ी की सुइयाँ धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थीं और हर मिनट किसी नए संकट की आशंका लेकर आ रहा था। ऑपरेशन 22 घंटे तक चला। इस दौरान कई बार स्थिति बेहद नाजुक हो गई। कभी रक्तस्राव का खतरा बढ़ गया, तो कभी शिशुओं की नाजुक धड़कनों ने चिंता बढ़ा दी।

इन कठिन क्षणों में डॉ. कार्सन का धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बना। वे पूरे समय शांत और संतुलित रहे। उन्होंने अपनी टीम को भी यही संदेश दिया कि घबराहट नहीं, बल्कि संयम ही इस ऑपरेशन की कुंजी है। उनके चेहरे पर न तो भय था और न ही हड़बड़ी। हर निर्णय सोच-समझकर लिया गया। यही संयम पूरी टीम के लिए संबल बन गया। जब नेतृत्व शांत होता है, तो पूरी टीम का मनोबल स्वतः मजबूत हो जाता है, और यही यहां देखने को मिला।

आखिरकार, लंबे संघर्ष और अथक प्रयास के बाद वह ऐतिहासिक क्षण आया, जब दोनों शिशुओं को सुरक्षित रूप से अलग कर दिया गया। ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन थिएटर में उपस्थित हर व्यक्ति की आँखों में राहत और गर्व के आँसू थे। यह केवल दो बच्चों की जान बचाने का मामला नहीं था, बल्कि यह चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने वाला क्षण था। इस सफलता ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि जो कार्य असंभव प्रतीत होता है, वह भी सही नेतृत्व, धैर्य और टीमवर्क से संभव हो सकता है।

डॉ. बेंजामिन कार्सन का यह कारनामा चिकित्सा इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वह संदेश है, जो यह घटना मानव समाज को देती है। यह कहानी बताती है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हों, यदि हम धैर्य बनाए रखें, स्वयं पर विश्वास रखें और एकजुट होकर प्रयास करें, तो कोई भी चुनौती हमें पराजित नहीं कर सकती। डॉ. कार्सन का जीवन इस सत्य की सशक्त मिसाल है कि धैर्य केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति का नाम है। यही शक्ति अंततः कामयाबी को जन्म देती है।

## विकसित भारत की राह के रोड़े, सरकारी दखल का होता है दुष्प्रभाव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नव वर्ष के आगमन के ठीक पहले पिछले वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है। इसके उपरांत उन्होंने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच 'प्रगति' की बैठक में सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला सहित विभिन्न क्षेत्रों की पांच महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की।

इस बैठक में उन्होंने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सुधार, प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक परिवर्तन बेहद जरूरी बताए। प्रधानमंत्री ने 2025 में किए गए जिन महत्वपूर्ण सुधारों का उल्लेख किया था, उनमें जीएसटी में व्यापक बदलाव, बीमा क्षेत्र में सौ प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति, ग्रामीण रोजगार कानून मनेरगा में आमूलचूल परिवर्तन और श्रम संहिताओं को लागू करने और परमाणु ऊर्जा से जुड़े सुधारों का उल्लेख किया।

निःसंदेह जीएसटी में सुधार से आम आदमी को लाभ मिला है, लेकिन अन्य सुधारों का लाभ मिलने में समय लगेगा। मोदी सरकार विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सुधार करने के साथ नई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करती रही है। इनके जरिये उसने सुशासन स्थापित करने की कोशिश की है ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो और देश तेजी के साथ आगे बढ़े। इसमें संदेह नही कि प्रशासनिक कामकाज में सरकारी नियंत्रण कम होने और विभिन्न क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी से आम जनता को लाभ मिलता है, लेकिन यह भी सच है कि कोई भी देश सरकारी नियंत्रण के बिना नहीं चलता, लेकिन यह नियंत्रण एक सीमा तक ही होना चाहिए। अपने देश में सरकारी नियंत्रण कम करने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उनके अनुरूप कुछ ठोस होता हुआ नहीं दिखता और इसीलिए पश्चिमी देश अभी भी यह शिकायत करते हैं कि भारत में सरकारी नियंत्रण अधिक है।

वे इस नियंत्रण को सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। इसी तरह विदेशी निवेशक भी कारोबारी सुगमता में तमाम सुधार होने के बाद भी भारत में काम करने में बाधाएं देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह शिकायत करती ही रहती हैं कि भारत में कोई उद्योग-व्यापार स्थापित करना अभी भी कठिन बना हुआ है, क्योंकि कदम-कदम पर सरकारी अनुमति की आवश्यकता पड़ती है।

मोदी सरकार की ओर से पिछले 11 सालों में उद्योग-व्यापार स्थापित और उन्हें संचालित करने में सरकारी दखल को कम करने के तमाम कदम उठाए जाने के बाद भी स्थितियां वैसी नहीं बन सकी हैं, जैसी बननी चाहिए। इस मामले में बात केवल केंद्र सरकार की ही नहीं, राज्य सरकारों की भी है। देश के सभी राज्यों का रवैया उद्योग एवं व्यापार के बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता और इसीलिए विकसित भारत के लक्ष्य में बाधाएं खड़ी हुई दिखती हैं।

यह एक तथ्य है कि विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए देश में जैसी कारोबारी सुगमता होनी चाहिए, वैसी नहीं है। कारोबारी सुगमता केवल होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि वह दिखनी भी चाहिए- खास तौर पर कारोबारियों को। इसी तरह सरकारी तंत्र को जन समस्याओं के समाधान में तत्पर दिखना चाहिए। अधिकांश मामले में इस तत्परता का अभाव ही दिखता है। निःसंदेह यह आशा की जा रही है कि इस नए वर्ष में भी सुधारों का सिलसिला कायम रहेगा। जनता और उद्योग-व्यापार जगत उन क्षेत्रों में सुधार की खास तौर पर उम्मीद कर रहा है, जहां उनकी गति धीमी है। बतौर उदाहरण शहरी ढांचे को ठीक करने के लिए जैसे कदम उठाए जाने आवश्यक हो गए हैं, उनमें देरी नहीं की जानी चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि नगर निकायों के कामकाज में अपेक्षित सुधार न होने से शहरी नागरिकों की समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं।

हमारे शहर आबादी के बोझ तले दब रहे हैं और उनका ढांचा चरमरा रहा है। बात चाहे सीपीडब्ल्यूडी की हो या पीडब्ल्यूडी की, वे ढंग की सड़कें भी नहीं बना पा रहे हैं। यही स्थिति नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले अन्य विभागों की भी है। उनकी ओर से किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता ठीक नहीं हो पा रही है। उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव भी व्याप्त है। यह तब है, जब सब जानते हैं कि शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं। अपने देश में समस्या केवल सरकारी कामकाज में गुणवत्ता के अभाव की ही नहीं है। यह अभाव उद्योग-व्यापार जगत में भी देखने को मिलता है। यह समझा जाना चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की कामकाज की गुणवत्ता ठीक करके ही विकसित भारत की नींव को मजबूत किया जा सकता है। जब सरकारी कामकाज दोयम दर्जे का होता है, तब उसका दुष्प्रभाव कहीं अधिक होता है, क्योंकि हर कहीं सरकारी दखल है और सरकारें सबसे बड़ी नियोक्ता हैं। विडंबना यह है कि औसत सरकारी कर्मियों का काम न तो पारदर्शी ढंग से होता है और न ही जवाबदेही के साथ। गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के बजाय जुगाड़ संस्कृति पर जोर दिया जाता है। दुर्भाग्य यह है कि देश में कम ही निजी उद्योग हैं, जहां गुणवत्ता और उत्पादकता को प्राथमिकता दी जाती है। यह एक तथ्य है कि भारत के बहुत कम उत्पाद विश्वस्तरीय गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। यदि सरकार अपने हर काम की गुणवत्ता ठीक करने को प्राथमिकता दे तो उसका प्रभाव निजी क्षेत्र पर भी पड़ेगा।

सरकारी क्षेत्र में अपेक्षित बदलाव तभी संभव है, जब देश की नौकरशाही के सोच में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। समस्या यह है कि फिलहाल सरकार के एजेंडे पर यह दिख नहीं रहा है। नौकरशाही में सुधार की जो प्रतीक्षा की जा रही है, वह इस नए वर्ष पूरी होनी चाहिए। नौकरशाही को अपने कामकाज के तौर-तरीकों के साथ अपनी मानसिकता भी बदलनी चाहिए। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि भी अपने काम का तरीका और सोच बदलें। यह भी समय की मांग है कि आम जनता भी अपना कार्य-व्यवहार बदले।

उसे अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने के साथ ही कर्तव्यों के प्रति भी सजग होना चाहिए। क्या कभी इसकी चर्चा होती है कि एक नागरिक के तौर पर हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं? देश के हर व्यक्ति को, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या फिर कारोबारी या फिर श्रमिक अथवा अन्य कोई, अपना काम इस तरह करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिससे विकसित भारत की नींव मजबूत हो।

अभियान

## ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती: पौराणिक रहस्य, दैवी दंड और मानव जीवन के लिए गहन संदेश

हिंदू धर्म की त्रिदेव परंपरा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि, पालन और संहार के तीन मूल स्तंभ माना गया है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, जिनसे सृजन की पहली चेतना उत्पन्न हुई। उन्हीं के संकल्प से आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पर्वत, नदियाँ, वनस्पतियाँ और समस्त जीव-जगत का विस्तार हुआ। वेदों और पुराणों में ब्रह्मा को आदिदेव कहा गया है, जिनके बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। इसके बावजूद यह एक गहरा और रहस्यमय प्रश्न है कि जिन ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, उनकी पूजा आज लगभग विलुप्त क्यों है। भारतवर्ष में शिव और विष्णु के असंख्य मंदिर मिल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का नाम लेते ही केवल राजस्थान के पुष्कर का मंदिर स्मरण में आता है। यह स्थिति केवल समय के साथ बदली हुई परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहन पौराणिक कथा, दैवी दंड और धर्म का कठोर नैतिक संदेश छिपा हुआ है।

पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का दायित्व सौंपा गया, तब उन्होंने अत्यंत संतुलित, सुंदर और नियमबद्ध सृष्टि की रचना की। प्रकृति के प्रत्येक तत्व में उन्होंने चेतना का संचार किया। इसी क्रम में उन्होंने एक अद्वितीय सौंदर्य से युक्त स्त्री की सृष्टि की, जिनका नाम शतरूपा रखा गया। शतरूपा केवल बाहरी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नहीं थीं, बल्कि विवेक, पवित्रता और सृजनात्मक चेतना का प्रतीक थीं। वे स्वयं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं और सृष्टि के विस्तार में उनकी सहचरी मानी जाती थीं।

किंतु यही सृष्टि की श्रेष्ठ रचना ब्रह्मा जी के लिए परीक्षा बन गई। पुराणों के अनुसार, ब्रह्मा जी अपनी ही रचना के सौंदर्य से मोहित हो गए। यह मोह सामान्य आकर्षण नहीं था, बल्कि सृष्टि की मर्यादा और पितृ-संबंध की पवित्रता को भंग करने वाला भाव था। शतरूपा जब जिस दिशा में जातीं, ब्रह्मा जी की दृष्टि अनायास ही उनका पीछा करने लगती। शतरूपा इस स्थिति से व्याकुल और असहज होने लगीं, क्योंकि वे ब्रह्मा जी को अपने पिता के समान मानती थीं। उनसे बचने के लिए वे कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर और कभी दक्षिण दिशा की ओर जाने लगीं।

कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों के साथ एक पाँचवाँ सिर उत्पन्न कर लिया, ताकि वे हर दिशा में शतरूपा को देख सकें। यह केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि जब चेतना पर मोह हावी हो जाता है, तब व्यक्ति अपनी शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग करने लगता है। सृष्टि के रचयिता द्वारा किया गया यह आचरण धर्म, मर्यादा और नैतिकता के स्पष्ट उल्लंघन के रूप में देखा गया। यह अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि इससे पूरी सृष्टि की नैतिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती थी।

जब भगवान शिव ने यह दृश्य देखा, तो उन्हें यह अत्यंत अधार्मिक और अनुचित प्रतीत हुआ। शिव केवल संहार के देवता नहीं हैं, वे धर्म, संतुलन और नैतिक अनुशासन के रक्षक भी हैं। उन्हें यह भय हुआ कि यदि स्वयं सृष्टि का रचयिता ही मर्यादा भंग करेगा, तो मनुष्य और अन्य जीवों के लिए धर्म का पालन कैसे संभव होगा। इसी कारण शिव ने अपने उग्र रूप भैरव को प्रकट किया और आदेश दिया कि ब्रह्मा जी के पाँचवें सिर को काट दिया जाए। भैरव ने बिना विलंब इस आदेश का पालन किया और ब्रह्मा जी का पाँचवाँ सिर पृथक हो गया।

पाँचवाँ सिर कटते ही ब्रह्मा जी का अहंकार और मोह चूर-चूर हो गया। उन्हें अपनी भूल का गहरा बोध हुआ और उन्होंने शिव से क्षमा याचना की। उन्होंने स्वीकार किया कि सृष्टि की रचना जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी मर्यादा की रक्षा भी है। शिव ने ब्रह्मा जी को नष्ट नहीं किया, क्योंकि सृष्टि के संतुलन के लिए उनका अस्तित्व आवश्यक था, लेकिन दंड अवश्य दिया। मान्यता है कि इसी दंड के रूप में ब्रह्मा जी को पृथ्वी पर पूजा से वंचित कर दिया गया। वे सृष्टि के रचयिता बने रहे, परंतु लोक में उनकी उपासना का अधिकार समाप्त कर दिया गया।

यही कारण है कि कालांतर में विष्णु जी लोकपाल, करुणा और संरक्षण के प्रतीक बनकर पूजे गए और शिव संहार के साथ-साथ मोक्षदाता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ब्रह्मा जी का स्थान सृष्टि के प्रारंभिक चरण तक सीमित रह गया। पूजा परंपराओं में उनका स्थान धीरे-धीरे गौण होता चला गया। राजस्थान के पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर को उनका एकमात्र प्रमुख मंदिर माना जाता है। यह मंदिर भी एक अलग पौराणिक प्रसंग से जुड़ा है, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहां यज्ञ किया था, इसलिए यहां उनकी पूजा संभव हुई। लेकिन व्यापक रूप से ब्रह्मा पूजा के अभाव का मुख्य कारण यही दैवी दंड माना जाता है।

कुछ विद्वान इस कथा को प्रतीकात्मक दृष्टि से भी देखते हैं। उनके अनुसार ब्रह्मा सृजन के प्रतीक हैं और सृजन एक बार पूर्ण हो जाने के बाद निरंतर पूजा का विषय नहीं रहता। विष्णु और शिव जीवन के सतत चलने वाले पक्षों—पालन और परिवर्तन—का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनकी पूजा अधिक प्रचलित हो गई। फिर भी लोकमान्यता और पुराणों में ब्रह्मा जी के दंड की कथा ही सबसे प्रभावी मानी जाती है।

यह पौराणिक प्रसंग केवल देवताओं की कहानी नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए एक गहन और कठोर संदेश भी है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान, शक्ति और सृजन क्षमता कितनी भी महान क्यों न हो, यदि उसमें मर्यादा और आत्मसंयम न हो, तो वह पतन का कारण बन सकती है। ब्रह्मा जी जैसे महान देवता भी मोह के कारण दंड के भागी बने, तो मनुष्य को कितनी सावधानी रखनी चाहिए, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

यह कथा यह भी बताती है कि पद, अधिकार और सम्मान स्थायी नहीं होते। वे धर्म और आचरण पर निर्भर करते हैं। यदि आचरण गिर जाता है, तो अधिकार भी छिन सकता है। मोह और आसक्ति सबसे बड़े शत्रु हैं, जो विवेक को ढक लेते हैं और व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाते हैं। आत्मसंयम, विवेक और मर्यादा ही धर्म का वास्तविक आधार हैं।

ब्रह्मा जी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि सृष्टि रचना से अधिक महत्वपूर्ण है सृष्टि की मर्यादा की रक्षा। बिना मर्यादा के सृजन भी विनाश का कारण बन सकता है। यही कारण है कि हिंदू दर्शन में केवल शक्ति या ज्ञान की नहीं, बल्कि संयम और नैतिकता की भी सर्वोच्चता मानी गई है। ब्रह्मा जी की पूजा का अभाव हमें निरंतर यह स्मरण कराता है कि धर्म केवल कर्म से नहीं, बल्कि सही आचरण से जीवित रहता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

# ताइवान पर चीन का कड़ा और स्पष्ट रुख: 'एकीकरण तय है, अलगाव की कोई संभावना नहीं', बीजिंग ने फिर दोहराई संप्रभुता की लाइन

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली/बीजिंग। ताइवान को लेकर चीन ने एक बार फिर बेहद सख्त और दो-टूक संदेश देते हुए अपने आधिकारिक रुख को सार्वजनिक रूप से दोहराया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने साफ शब्दों में कहा है कि ताइवान ऐतिहासिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से चीन का अभिन्न हिस्सा रहा है और इस सच्चाई पर कोई भ्रम या विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन का पुनः एकीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जो अपरिहार्य है, और इसमें अलगाव या स्वतंत्रता की कोई गुंजाइश नहीं है।

राजदूत शू फेइहोंग ने कहा कि अक्टूबर 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद से ही चीन की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय पहचान पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि 1949 में सत्ता परिवर्तन के साथ रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार की जगह पीआरसी ने ली और वही पूरे चीन का एकमात्र वैध प्रतिनिधि बना। उनके अनुसार, यह केवल सरकार में बदलाव था, न कि किसी नए देश का निर्माण। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत 'चीन' की पहचान, उसकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पहले जैसी ही बनी रही, जिसमें ताइवान भी शामिल है।

चीनी राजदूत ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर यह भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि 1949 के बाद चीन दो हिस्सों में बंट गया, लेकिन यह पूरी तरह गलत और भ्रामक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गृहयुद्ध और बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण ताइवान जलडमरूमध्य के दोनों किनारों के बीच राजनीतिक टकराव जरूर बना रहा, लेकिन इससे चीन की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ा। उनके मुताबिक चीन कभी विभाजित नहीं हुआ और न ही भविष्य में होगा।

ताइवान का सवाल केवल आंतरिक राजनीतिक स्थिति से जुड़ा है, न कि किसी अलग देश के अस्तित्व से।

शू फेइहोंग ने दो टूक कहा कि ताइवान कभी भी एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र नहीं रहा है—न अतीत में, न वर्तमान में और न ही भविष्य में। उन्होंने कहा कि इतिहास, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और अंतरराष्ट्रीय कानून सभी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ देश और ताकतें इस मुद्दे को जानबूझकर जटिल बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इससे वास्तविकता नहीं बदलेगी।

ताइवान की मौजूदा सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी पर परोक्ष हमला करते हुए चीनी राजदूत ने कहा कि वहां की सरकार चाहे कितने भी बयान दे या अलगाववादी कदम उठाने की कोशिश करे, उससे ताइवान का भविष्य नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि डीपीपी की नीतियां केवल तनाव और अस्थिरता को बढ़ावा देती हैं, लेकिन चीन के पुनः एकीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया को रोक नहीं सकतीं। शू फेइहोंग के अनुसार, चीन की सरकार और वहां की जनता इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट हैं और किसी भी तरह के अलगाववादी प्रयासों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

राजदूत ने यह भी संकेत दिया कि चीन ताइवान के साथ शांतिपूर्ण पुनः एकीकरण को प्राथमिकता देता है, लेकिन यदि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दी गई, तो बीजिंग अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि चीन की नीति स्पष्ट है—एक चीन का सिद्धांत किसी भी हाल में समझौते का विषय नहीं हो सकता।

चीन के इस बयान को ऐसे समय में अहम माना जा रहा है, जब ताइवान को लेकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है और कई वैश्विक शक्तियां इस मुद्दे पर अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं। शू फेइहोंग का यह बयान न केवल ताइवान को संदेश देता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी यह स्पष्ट करता है कि चीन इस मुद्दे पर किसी भी तरह की नरमी या अस्पष्टता के पक्ष में नहीं है।

कुल मिलाकर, चीन ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि ताइवान उसके लिए कोई बाहरी या अंतरराष्ट्रीय विवाद नहीं, बल्कि आंतरिक मामला है। बीजिंग का मानना है कि समय के साथ पुनः एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी और किसी भी तरह के अलगाववादी सपनों का अंत तय है। इस बयान के बाद यह स्पष्ट है कि ताइवान का मुद्दा आने वाले समय में भी चीन की विदेश और सुरक्षा नीति के केंद्र में बना रहेगा और इस पर उसका रुख पहले की तरह अडिग रहेगा।

## गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा गांधीनगर में जलजन्य टायफाइड की स्थिति को लेकर प्रशासन को युद्धस्तर पर कार्यवाही के आदेश

- श्री अमित शाह ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, जिला कलेक्टर तथा महानगर पालिका आयुक्त के साथ चर्चा कर आवश्यक सुझाव दिए
- श्री अमित शाह ने मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा त्वरित और सटीक उपचार सुनिश्चित करने तथा अस्पताल में परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के आदेश दिए
- श्री अमित शाह ने लीकेज की तत्काल मरम्मत करने और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के फैलाव को रोकने के लिए आसपास के क्षेत्रों में पाइपलाइन की सघन जांच के आदेश दिए

**(जीएनएस)**। गांधीनगर : गांधीनगर शहर के सेक्टर 24, 28 तथा आदिवाडा क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण दूषित पानी से बच्चों एवं नागरिकों में टायफाइड के मामले सामने आए हैं। इस संदर्भ में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद व केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, जिला कलेक्टर तथा महानगर पालिका आयुक्त के साथ निरंतर संपर्क में रहकर चर्चा की, वर्तमान स्थिति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की तथा मौजूदा परिस्थिति से निपटने के लिए युद्धस्तर पर कार्यवाही करने के सुझाव दिए हैं।

श्री अमित शाह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर टायफाइड से प्रभावित बच्चों एवं नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा त्वरित और सटीक उपचार सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं, साथ ही गांधीनगर सिविल अस्पताल में पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों के लिए भोजन की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। श्री शाह ने लीकेज की तत्काल मरम्मत करने और इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का और फैलाव न हो, इसके लिए आसपास के क्षेत्रों में भी पाइप लाइन की सघन जांच करने के आदेश दिए हैं।

गांधीनगर शहर में संदिग्ध टायफाइड मामलों को लेकर सघन स्वास्थ्य व्यवस्था एवं सर्वेक्षण कार्यवाही शुरू की गई है। जिन क्षेत्रों से ये संदिग्ध मामले सामने आए हैं, उन सेक्टर 24, 26 और 28 तथा आदिवाडा क्षेत्रों में 75 हेल्थ टीमों द्वारा सर्वेक्षण किया गया है।

अब तक संदिग्ध टायफाइड के 113 मामले सामने आए हैं, जिनमें से उपचाराधीन मरीजों में से 19 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। शेष 94 मरीजों को गांधीनगर सिविल अस्पताल तथा सेक्टर 24 और 29 के यूएचसी में उपचार दिया जा रहा है तथा सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है। प्रभावित क्षेत्रों में 24×7 ओपीडी शुरू की गई है। जिन मरीजों का उपचार सिविल अस्पताल में किया जा रहा है, उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है।

गांधीनगर महानगर पालिका की सर्वेक्षण टीमों द्वारा अब तक 20,800 से अधिक घरों का सर्वे कर 90 हजार से अधिक जनसंख्या को कवर किया गया है। रोग रोकथाम के उपायों के अंतर्गत 30 हजार क्लोरीन टैबलेट और 20,600 ओआरएस पैकेट का वितरण किया गया है।

सर्वेक्षण टीमें घर-घर जाकर जागरूकता पत्रिकाओं का वितरण कर रही हैं तथा लोगों को पानी उबालकर पीने, बाहर का खाना न खाने और हाथों की स्वच्छता बनाए रखने जैसी जानकारियां प्रदान कर रही हैं।

रोग नियंत्रण के लिए पानी के सुपर क्लोरीनेशन की कार्यवाही को तेज किया गया है और पानी में क्लोरीन की मात्रा की नियमित जांच की जा रही है। महानगर पालिका प्रशासन द्वारा सोमवार तक 24×7 जलापूर्ति के स्विच ओवर की कार्यवाही की जाएगी।

इसके परिणामस्वरूप सुदूरवर्ती घरों तक भी उचित मात्रा में क्लोरीनयुक्त पानी पहुंचाया जा सकेगा।

रोग प्रभावित क्षेत्रों में जहां छोटे-बड़े लीकेज पाए गए हैं, उनकी मरम्मत भी तत्काल प्रभाव से की जा रही है।

महानगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर में पानीपुरी, रगड़ा पैटीस, बर्फ के गोले, शिकंजी सोडा तथा दूध से बने पेय पदार्थों की बिक्री की भी सघन जांच की जा रही है।

## सूरत सहित दक्षिण गुजरात में कड़ाके की ठंड का असर गहराया लगातार गिरते तापमान ने बदली जनजीवन की रफ्तार

**(जीएनएस)**। सूरत समेत पूरे दक्षिण गुजरात में सर्दी ने अब पूरी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। बीते कुछ दिनों से मौसम में आए बदलाव के कारण सुबह-सुबह और देर रात ठंड का तीखा अहसास होने लगा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या पर साफ नजर आ रहा है। हल्की ठंड के दौर से निकलकर अब मौसम ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जहां लोगों को गर्म कपड़ों के सहारे ही बाहर निकलना पड़ रहा है। सड़कों पर सुबह के समय कुहासे जैसी ठंडक और रात के वक्त ठंडी हवाओं ने सूरतवासियों को यह एहसास करा दिया है कि इस बार सर्दी देर से सही, लेकिन पूरे असर के साथ आई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को सूरत शहर का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 15.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बीते दिन की तुलना में अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में यह क्रमिक लेकिन लगातार गिरावट खासतौर पर रात के समय ज्यादा महसूस की जा रही है। जैसे-जैसे सूरज ढलता है, ठंड तेजी से बढ़ती जाती है और देर रात तक सर्द हवाएं लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर देती हैं।

फिलहाल सूरत शहर में उत्तर दिशा से करीब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर अब दक्षिण गुजरात तक पहुंच रहा है। वहां से आने वाली ठंडी हवाएं वातावरण की नमी के साथ मिलकर ठंड को और अधिक तीव्र बना रही हैं। हवा की दिशा और मौजूदा मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ठंड का यह सिलसिला बना रहेगा और तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद राहत मिलने की संभावना कम है। ठंड बढ़ने के साथ ही सूरत के बाजारों और सड़कों पर भी इसका असर दिखने लगा है। लोग सुबह की सैर पर निकलते समय स्वेटर, जैकेट और शॉल में लिपटे नजर आ रहे हैं। दफ्तर और कारखानों में काम पर जल्दी निकलने वाले कर्मचारियों के लिए गर्म कपड़े अब अनिवार्य हो गए हैं। वहीं, रात के समय फुटपाथों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जलाते या हीटर का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। ठंड के कारण देर रात तक चहल-पहल रहने वाले कई इलाकों में भी अब अपेक्षाकृत सन्नाटा पसरा रहने लगा है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक सूरत और दक्षिण गुजरात में ठंड का यही दौर जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है, जिससे साफ है कि फिलहाल सर्दी से राहत के आसार नहीं हैं। ऐसे में डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाने पर जोर दिया जा रहा है।

## साबरमती-खोडियार के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 240 (त्रागढ रोड फाटक) बंद रहेगा

**(जीएनएस)**। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर साबरमती-खोडियार स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे क्रॉसिंग नं. 240 किमी 773/4-6 (त्रागढ रोड फाटक) 05 जनवरी 2026 को रात्रि 00.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक तथा दोपहर 15.00 बजे से सायं 18.00 बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रहेगा।

सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान रेलवे क्रॉसिंग नंबर 241 अंडरपास वाया गोदरेज गार्डन सिटी और एस. जी. हाईवे से आवागमन कर सकते हैं।

## रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अहमदाबाद द्वारा ऑटो चालकों पर बड़ी कार्रवाई

**(जीएनएस)**। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों द्वारा यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं निर्धारित मानकों से अधिक किराया वसूलने संबंधी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रेलवे सुरक्षा बल, अहमदाबाद द्वारा समय-समय पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज 04.01.2025 को रेलवे सुरक्षा बल, अहमदाबाद द्वारा विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान कुल 6 ऑटो चालकों के ऑटो जप्त किए गए तथा संबंधित ऑटो चालकों के विरुद्ध रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। रेलवे सुरक्षा बल, अहमदाबाद यात्रियों की सुरक्षा, सम्मान एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भविष्य में भी यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा या अनियमितता न हो, इसके लिए ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

## दीन सहायक विद्या मंदिर बमरोली में बच्चों की मुस्कान और उत्साह से सजा आनंद मेला, निःशुल्क शिक्षा केंद्र में उमड़ा उल्लास

**(जीएनएस)**। सूरत के बमरोली क्षेत्र में स्थित हिन्दू सनातन पब्लिक सेवा चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित दीन सहायक विद्या मंदिर निःशुल्क शिक्षा केंद्र में रविवार, 4 जनवरी 2026 को बच्चों के लिए आनंद मेला एवं फन फेयर का भव्य और उल्लासपूर्ण आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे विद्यालय परिसर में बच्चों की खुशियों, रंग-बिरंगे स्टॉलों और उमंग से भरा माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के संस्थापक पंडित गिरिजा शंकर उपाध्याय द्वारा दीप प्रज्वलन एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई, जिसके बाद विधिवत रूप से आनंद मेले का शुभारंभ हुआ।

आनंद मेले में विद्यालय के बच्चों ने अपने-अपने घरों से विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लाकर स्वयं के स्टॉल लगाए। बच्चों ने न केवल भोजन बनाया, बल्कि उसकी साज-सज्जा, बिक्री और ग्राहकों से संवाद की जिम्मेदारी भी पूरी गंभीरता और उत्साह के साथ निभाई। मेले में पानीपुरी, भेलपुरी, नूडल्स, पिज़्ज़ा, मंचूरियन, आलू पूरी, चाय, कॉफी, दूध, पकोड़ा, समोसा, जलेबी, लड्डू, खमन, पॉपकॉर्न, पास्ता और पावभाजी जैसे अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने रहे। स्टॉलों पर खरीदारी करने के लिए बच्चों, अभिभावकों और आगंतुकों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली, जिससे पूरे परिसर में मेले जैसा जीवंत वातावरण बन गया।

इस आयोजन में स्टॉल लगाने वाले बच्चों में अंशिका, अनामिका, नितेश, आदर्श, साक्षी, अंश, रागिनी, सिद्धि, अयांश, कनक मोदी और अनुष्का सहित कई छात्र-छात्राएं शामिल रहीं। सभी बच्चों ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने-अपने स्टॉल संभाले और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेहनत और रचनात्मकता का परिचय दिया। बच्चों का उत्साह, मुस्कान और आपसी सहयोग पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता रहा। पूरे आयोजन का सफल संचालन शिक्षक आदित्य यादव एवं आरती विश्वकर्मा द्वारा किया गया, जिन्होंने बच्चों को हर कदम पर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान किया।

संस्था के प्रमुख पंडित गिरिजा शंकर उपाध्याय ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों को केवल मनोरंजन ही नहीं देते, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाते हैं। उन्होंने बताया कि आनंद मेला जैसे कार्यक्रम बच्चों को व्यावहारिक रूप से अर्थशास्त्र, धन प्रबंधन, मेहनत की कीमत और संसाधनों के सही उपयोग की समझ प्रदान करते हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क शिक्षा केंद्र में पढ़ने वाले इन नन्हे-मुन्ने बच्चों की सक्रिय सहभागिता और लगन यह साबित करती है कि सही मार्गदर्शन मिलने पर हर बच्चा आगे बढ़ सकता है।

पूरे कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। अभिभावकों और उपस्थित अतिथियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। दीन सहायक विद्या मंदिर में आयोजित यह आनंद मेला न केवल एक मनोरंजक कार्यक्रम रहा, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा, आत्मनिर्भरता और जीवन कौशल को निखारने की दिशा में एक प्रेरणादायक और यादगार पहल बनकर उभरा।

# राइसिन जहर से दहशत फैलाने की साजिश अब एनआईए करेगी देशव्यापी जांच

**(जीएनएस)**। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानी जा रही राइसिन जहर आधारित आतंकी साजिश की जांच अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के हाथों में सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) से लेकर एनआईए को ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला इस साजिश की अंतरराष्ट्रीय कड़ियों, आतंकी संगठनों से जुड़े संपर्कों और संभावित बड़े हमले की आशंका को देखते हुए लिया गया है।

गुजरात एटीएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज इस संवेदनशील मामले को एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया है। अब एनआईए इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच करेगी और यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि इस साजिश का दायरा कितना बड़ा था और इसके पीछे कौन-कौन से आतंकी संगठन या विदेशी ताकतें सक्रिय थीं।

गौरतलब है कि गुजरात एटीएस ने पिछले साल 9 नवंबर को इस साजिश का भंडाफोड़ करते हुए तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में हैदराबाद के मूल निवासी डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद, उत्तर प्रदेश के आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम शामिल हैं। इन तीनों पर हथियारों और रसायनों की मदद से बड़े पैमाने पर आतंकी हमला करने की साजिश रचने का आरोप है। एटीएस ने इनके खिलाफ यूएपीए के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम के तहत भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था।

जांच के दौरान सामने आया था कि डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद को 7 नवंबर को गांधीनगर के अडालज इलाके के पास से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से दो अत्याधुनिक ग्लॉक पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और चार लीटर अरंडी का तेल बरामद किया गया था। यह बरामदगी अपने आप में चौंकाने वाली थी, क्योंकि अरंडी के तेल से राइसिन नामक अत्यंत घातक जहर तैयार किया जा सकता है। राइसिन को दुनिया के सबसे खतरनाक विषैले पदार्थों में गिना जाता है और इसकी बेहद कम मात्रा भी जानलेवा साबित हो सकती है।

एटीएस की शुरुआती जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि डॉ. सैयद चीन से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर चुका है और उसे रसायन विज्ञान तथा मेडिकल ज्ञान का अच्छा खासा अनुभव है। इसी ज्ञान का इस्तेमाल वह आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए कर रहा था। अधिकारियों के अनुसार, वह राइसिन जहर तैयार करने के लिए आवश्यक शोध कर चुका था, उसने उपकरण और कच्चा माल जुटा लिया था और प्रारंभिक रासायनिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। अगर समय रहते उसे नहीं रोका जाता, तो यह साजिश बड़े पैमाने पर जान-माल के नुकसान का कारण बन सकती थी।

इस मामले में उत्तर प्रदेश के आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम की गिरफ्तारी बनासकांठा जिले से हुई थी। दोनों पर आरोप है कि वे डॉ. सैयद को अवैध हथियार पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ स्थानीय स्तर की साजिश नहीं थी, बल्कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। अधिकारियों ने पहले ही यह पुष्टि की थी कि डॉ. सैयद का हैंडलर अबू खदीजा अफगानिस्तान का रहने वाला है और वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (आईएसकेपी) से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा डॉ. सैयद के पाकिस्तान में मौजूद कई व्यक्तियों से संपर्क में होने की भी जानकारी सामने आई थी। इन तथ्यों ने जांच एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी थी, क्योंकि इससे यह संकेत मिला कि भारत के भीतर किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश विदेशी सरपरस्ती में रची जा रही थी।

राइसिन जैसे रासायनिक हथियार का इस्तेमाल पारंपरिक बम या गोलीबारी से अलग और कहीं अधिक खतरनाक माना जाता है। यह एक ऐसा जहर है, जिसकी पहचान करना मुश्किल होता है और जिसके इस्तेमाल से दहशत का माहौल पैदा किया जा सकता है। इसी वजह से इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है।

## नए वर्ष की पहली किरण के साथ अनुशासन, सेवा और स्वास्थ्य का संकल्प, सूरत होमगार्ड्स ने सामूहिक सूर्य नमस्कार से दिया सकारात्मक संदेश

**(जीएनएस)**। नए वर्ष के शुभारंभ को अर्थपूर्ण और प्रेरणादायी बनाने के उद्देश्य से सूरत शहर होमगार्ड्स द्वारा "नए वर्ष की प्रथम सूर्य किरण को नमस्कार" कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन केवल एक योग कार्यक्रम नहीं, बल्कि अनुशासन, सेवा भावना और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति सामूहिक संकल्प का प्रतीक बनकर उभरा। यह कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक एवं मुख्य पुलिस अधिकारी (पुलिस रिफॉर्म्स), कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स पियूष पटेल तथा सीनियर स्टाफ ऑफिसर मुख्यालय मनीष त्रिवेदी के मार्गदर्शन में, गुजरात राज्य योग बोर्ड, गुजरात सरकार के अनुरोध पर पूरे राज्य में एक साथ आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत सूरत शहर में भी व्यापक सहभागिता देखने को मिली। सूरत शहर के जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुल वी. शिरोया के नेतृत्व में शहर की सभी ज़ोन और यूनिटों में एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रातःकाल वातावरण में जब नए वर्ष की पहली सूर्य किरण धरती पर उतरी, उसी क्षण सूर्य प्रार्थना और संगठन मंत्र के पाठ के साथ कार्यक्रम की शुभ शुरुआत की गई। अनुशासनबद्ध पंक्तियों में खड़े होमगार्ड्स का समवेत स्वर और समन्वित योग अभ्यास पूरे वातावरण को ऊर्जा और सकारात्मकता से भर रहा था। यह दृश्य न केवल शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि मानसिक एकाग्रता और सामूहिक एकता का भी सशक्त उदाहरण बन गया।

कार्यक्रम में सूरत शहर की विभिन्न ज़ोन एवं यूनिटों से बड़ी संख्या में होमगार्ड्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ए ज़ोन से 123, बी ज़ोन से 145, सी ज़ोन से 231, डी ज़ोन से 107, रांदेर यूनिट से 154, सचिन यूनिट से 156 तथा महिला यूनिट से 120 महिला होमगार्ड्स ने सहभागिता की। इस प्रकार कुल 1432 होमगार्ड्स ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर नए वर्ष का स्वागत किया। महिला यूनिट की ओर से स्टाफ ऑफिसर (महिला) धर्मिष्ठा मानकिया की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक प्रेरक बनाया, वहीं विभिन्न ज़ोन के ऑफिसर कमांडिंग द्वारा अपने-अपने यूनिटों का नेतृत्व अनुशासन और समर्पण के साथ किया गया।

इस अवसर पर जिला कमांडेंट डॉ. प्रफुल वी. शिरोया ने सूर्य नमस्कार के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार केवल एक योग क्रिया नहीं, बल्कि सम्पूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। यह शरीर को भीतर से शुद्ध करता है, रक्त परिसंचरण को सुदृढ़ बनाता है, हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सहायक होता है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स जैसे अनुशासित बल के लिए शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक संतुलन भी उतना ही आवश्यक है, और सूर्य नमस्कार दोनों को सशक्त करने का प्रभावी माध्यम है।

कार्यक्रम के दौरान सभी होमगार्ड्स ने हाथ जोड़कर 'स्वदेशी और संस्कृति' के संदेश को घर-घर तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया। यह संकल्प न केवल स्वास्थ्य, बल्कि भारतीय संस्कृति, योग परंपरा और आत्मनिर्भरता के विचार को जन-जन तक पहुंचाने की भावना को भी दर्शाता है। सूरत पुलिस सलाहकार समिति के सदस्य रमेशभाई दुधात, अनिलभाई सोजित्रा, हितेशभाई लाठिया एवं राजूभाई सूर्यदर्शनी ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम का अभिनंदन किया और होमगार्ड्स के इस प्रयास की सराहना की।

संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वय सेकंड कमांडेंट प्रणव ठाकर तथा योग बोर्ड सूरत जिला को-ऑर्डिनेटर नवनीत शेलडिया द्वारा किया गया। आयोजन को सफल बनाने में कृति बारडोलिया, भीमभाई बासेल, श्वेता लिंबाचिया, निमिषा शाह, अनीता चापनेरी, कोमल गज्जर, चैताली चौहान, राकेश मेहता, धर्मिष्ठा मेहता, हिना चावड़ा, संध्या पटेल एवं मयूरी मिस्त्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम की सफलता पर निरीक्षक-प्रशिक्षक जयदीप कातरिया ने गुजरात स्टेट योग बोर्ड, पत्रकार मित्रों तथा उपस्थित सभी जनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

कुल मिलाकर, सूरत होमगार्ड्स द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम नए वर्ष की शुरुआत को स्वास्थ्य, अनुशासन और सेवा भावना के साथ जोड़ने का एक प्रेरणादायी प्रयास साबित हुआ, जिसने यह संदेश दिया कि स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच के साथ ही समाज और राष्ट्र की सच्ची सेवा संभव है।

# वेनेजुएला में भूचाल, राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी से दुनिया में हलचल, ब्रुकलिन की कुख्यात जेल में रखा गया और UNSC ने बुलाई आपात बैठक

**(जीएनएस)।** न्यूयॉर्क/वाशिंगटन। वेनेजुएला की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में उस समय बड़ा भूचाल आ गया, जब राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की खबर सामने आई। अमेरिकी कार्रवाई के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जिसे अमेरिका की सबसे विवादित और कुख्यात जेलों में गिना जाता है। इस घटनाक्रम ने न केवल लैटिन अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया में तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दे दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इमरजेंसी बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिसमें अमेरिकी कदम और उसके अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।

ब्रुकलिन का मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर पहले से ही अपने खराब हालात और हाई-प्रोफाइल कैदियों के कारण सुर्खियों में रहा है। 1990 के दशक में बनी यह जेल समुद्र के किनारे एक औद्योगिक इलाके में स्थित है और यहां से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर की स्थिति को लेकर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं। वर्तमान में यहां करीब 1,300 कैदी बंद हैं, जिनमें मैनहट्टन और ब्रुकलिन की फेडरल अदालतों में मुकदमे का इंतजार कर रहे गैंगस्टर, ड्रग तस्कर और बड़े आर्थिक अपराधी शामिल हैं। इसी जेल में पहले जेफरी एपस्टीन की सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल, मशहूर गायक आर. केली और कुख्यात ड्रग कार्टेल लीडर इस्माइल जाम्बाडा गार्सिया जैसे चर्चित नाम भी रह चुके हैं।

बताया जा रहा है कि निकोलस मादुरो को शुरुआती दिनों में सुरक्षा कारणों से अलग-थलग रखा जा सकता है। हालांकि यदि बाद में उन्हें सामान्य कैदी क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया, तो वहां उन्हें अपने पुराने परिचित चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। इनमें वेनेजुएला के पूर्व खुफिया प्रमुख ह्यूगो कार्वाजल और अंतरराष्ट्रीय




अपराध गिरोहों से जुड़े कुछ अन्य कैदी शामिल बताए जा रहे हैं। जेल के भीतर हालात पहले भी हिंसा, झड़पों और यहां तक कि हत्याओं की घटनाओं के कारण सवालों के घेरे में रहे हैं। वर्ष 2024 में भी यहां कैदियों के बीच हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद जेल प्रशासन ने बिजली, पानी, हीटिंग और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के दावे किए थे।

मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिकी प्रशासन ने इसे एक बड़ी कार्रवाई बताया है। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वेनेजुएला में सैन्य अभियान चलाया गया और उसके बाद मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाइट हाउस की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हथकड़ी लगाए मादुरो अमेरिकी अधिकारियों को "हैप्पी न्यू ईयर" कहते हुए नजर आए। इसके बाद उन्हें USS इयो जिमा वॉरशिप के जरिए अमेरिका लाए जाने की जानकारी दी गई, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक नाटकीय बना दिया।

इस कार्रवाई के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को आपात बैठक बुलाने का फैसला किया है। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि अमेरिका की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और वैश्विक शांति के लिहाज से क्या मायने रखती है। कई देशों ने इस कदम पर चिंता जताई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इसे वेनेजुएला की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती हैं। कुछ अन्य देशों और नेताओं ने भी संयम और कूटनीतिक समाधान की जरूरत पर जोर दिया है।

इधर, वेनेजुएला के भीतर भी राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में मादुरो अस्थायी रूप से अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, इसलिए शासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस फैसले के बाद वेनेजुएला में सत्ता संतुलन और भविष्य की राजनीति को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं।

कुल मिलाकर, मादुरो की गिरफ्तारी ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नया तनाव बिंदु पैदा कर दिया है। जहां एक ओर अमेरिका इसे अपनी कार्रवाई की सफलता के रूप में पेश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कई देश इसे खतरनाक मिसाल मान रहे हैं, जो भविष्य में वैश्विक व्यवस्था को और जटिल बना सकती है। अब सबकी निगाहें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि इस अभूतपूर्व घटनाक्रम पर दुनिया क्या रुख अपनाती है और आगे का रास्ता किस दिशा में जाता है।

## प्रदेश सरकार शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव के लिए तैयार: मुख्यमंत्री सुक्खू

**(जीएनएस)।** शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे में बड़े बदलावों की योजना का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों को सीबीएसई के अधीन लाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ा रही है और इसके तहत अंग्रेजी और गणित विषयों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। ये स्पेशल इंस्ट्रक्टर बच्चों की सीखने की क्षमता और विषय में रुचि को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसके लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अमलैहड़ स्कूल को सीबीएसई का दर्जा प्रदान किया गया है और यहां राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें अगले साल से कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। अमलैहड़ समेत प्रदेश के चार चुनिंदा स्कूलों में मल्टीपल सब्जेक्ट सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुन सकें। शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि और प्राकृतिक खेती को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और इससे उत्पन्न फसलों की उच्च मूल्य पर खरीद सुनिश्चित कर रही है। उदाहरण के तौर पर हल्दी की खेती से किसान 90 रुपये प्रति किलो की दर से लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पांच कनाल भूमि पर हल्दी उगाकर एक किसान तीन लाख रुपये तक की आय अर्जित कर सकता है। इसके अलावा बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे चार कनाल भूमि पर युवा हर साल लगभग तीन लाख रुपये तक का शुद्ध लाभ कमा सकते हैं।

पेयजल और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने बड़े निवेश और सुधार की जानकारी दी। नादौन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पारंपरिक ब्लीचिंग पाउडर की जगह अत्याधुनिक यू.वी. टेक्नोलॉजी और ओजोनेशन प्रक्रिया से पानी की शुद्धिकरण की जा रही है, ताकि स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान ग्राम पंचायत अमलैहड़ में लगभग 60 लाख रुपये की लागत से निर्मित गुग्गा धाम एवं पार्क का उद्घाटन किया और क्षेत्रवासियों से संवाद किया। इसी क्रम में उन्होंने ग्राम पंचायत गौना के गांव पखरोल में लगभग 25 लाख रुपये की लागत से निर्मित श्री वैकुंठ धाम एवं पार्क का लोकार्पण किया। नादौन शहर के इंद्रपाल चौक पर स्वतंत्रता सेनानी इंद्रपाल की प्रतिमा एवं स्मारक का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य भी हाल ही में नगर परिषद द्वारा पूर्ण किया गया है, जिसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, प्राकृतिक खेती और नवीनीकरण परियोजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेश के विकास और नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने किसानों, युवाओं और छात्रों से अपील की कि वे इन पहल का लाभ उठाएं और राज्य के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास में योगदान दें।

## बल्लारी हिंसा पर सियासी संग्राम तेज, डीके शिवकुमार का भाजपा पर सीधा वार बोले- कांग्रेस की जीत पच नहीं रही, 'बल्लारी रिपब्लिक' का दौर लौटने नहीं देंगे

**(जीएनएस)।** बल्लारी, कर्नाटक। कर्नाटक के बल्लारी में कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प ने राज्य की राजनीति में जबरदस्त उबाल ला दिया है। इस घटना को लेकर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए भाजपा और उसके विधायक जी. जनार्दन रेड्डी पर सीधा हमला बोला है। शिवकुमार ने साफ शब्दों में कहा कि बल्लारी में हिंसा के पीछे राजनीतिक उकसावे की भूमिका है और भाजपा कांग्रेस की जीत को पचा नहीं पा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

डीके शिवकुमार ने कहा कि जब तक जनार्दन रेड्डी बल्लारी नहीं आए थे, तब तक शहर पूरी तरह शांत था। उन्होंने आरोप लगाया कि रेड्डी के आगमन के बाद ही माहौल बिगड़ा और तनाव फैलाया गया। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस मामले में पुलिस व जांच एजेंसियां पूरी स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जांच में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा और जो भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



मुख्यमंत्री के गृह कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीके शिवकुमार ने पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि बल्लारी में पहली बार महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी, जो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवसर था। इस आयोजन की जिम्मेदारी कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी को दी गई थी। शिवकुमार ने सवाल उठाया कि यदि इस शुभ अवसर पर बैनर लगाए गए, तो इसमें आपत्ति की क्या बात थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा चाहे तो उनके घर के सामने भी अपने बैनर लगा सकती है, कांग्रेस को उससे कोई समस्या नहीं है।

डीके शिवकुमार ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे कांग्रेस की राजनीतिक सफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फिर से उस पुराने दौर को लौटाने का सपना देख रहे हैं, जिसे कभी 'बल्लारी रिपब्लिक' कहा जाता था, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। शिवकुमार ने दो टूक कहा कि कांग्रेस सरकार किसी भी हाल में उस अराजक और डर के माहौल को वापस नहीं आने देगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अवैध रूप से रखी गई निजी बंदूकें जब्त कर ली गई हैं और आने वाले समय में नियमों को और अधिक सख्त किया जाएगा, ताकि आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे।

जनार्दन रेड्डी द्वारा खुद पर हत्या की साजिश रचे जाने के दावे पर डीके शिवकुमार ने तीखा तंज कसा। उन्होंने रेड्डी को 'ड्रामा मास्टर' बताते हुए कहा कि वे फिल्म निर्माता भी हैं, इसलिए अभिनय करना उनके स्वभाव में शामिल है। शिवकुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि जिसके पास सैकड़ों सुरक्षाकर्मी हों, जिसने अपने चारों ओर किले जैसी सुरक्षा व्यवस्था बना रखी हो, उसे भला कौन मार सकता है। उन्होंने दावा किया कि असल में डर रेड्डी परिवार में नहीं, बल्कि बल्लारी की आम जनता में है, जिसे बार-बार इस तरह की घटनाओं से सहमाया जाता है।

इस बीच भाजपा विधायक जी. जनार्दन रेड्डी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपने लिए जेड-श्रेणी सुरक्षा की मांग की है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि बल्लारी में हुआ हमला एक पूर्व-नियोजित साजिश का हिस्सा था और उनकी जान को गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार के लिए राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण शहर की शांति और कानून-व्यवस्था है। उन्होंने बल्लारी के एसपी के निलंबन का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिवकुमार ने भरोसा दिलाया कि सरकार हालात पर पूरी नजर रखे हुए है और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बल्लारी हिंसा ने एक बार फिर कर्नाटक की राजनीति में सत्ता संघर्ष, पुराने प्रभाव और नए शासन के बीच टकराव को उजागर कर दिया है। जहां कांग्रेस इसे अपनी जीत से बौखलाए विपक्ष की साजिश बता रही है, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और प्रशासनिक कदम यह तय करेंगे कि यह मामला केवल स्थानीय तनाव बनकर रह जाता है या राज्य की राजनीति में एक बड़े टकराव का रूप लेता है।

## भारत-नेपाल सीमा पर भड़का सांप्रदायिक तनाव, सोशल मीडिया के एक वीडियो ने बिगाड़ा माहौल, बीरगंज-धनुषा में हिंसक झड़पें

**(जीएनएस)।** बीरगंज, नेपाल। भारत-नेपाल की खुली सीमा से सटे इलाकों में रविवार को उस समय सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक कथित आपत्तिजनक वीडियो ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। देखते ही देखते हालात बीरगंज और धनुषा जिले में बेकाबू हो गए और विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। सड़कों पर टायर जलाए गए, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और प्रशासन को हालात काबू में लाने के लिए आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा।

घटना की शुरुआत धनुषा जिले के कमला नगरपालिका अंतर्गत सखुवा मरन क्षेत्र से बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार यहां एक स्थानीय मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना हुई, जिसके बाद इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री दिखाए जाने का आरोप है। वीडियो के फैलते ही इलाके में तनाव बढ़ गया और गुस्साए लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई।

स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया है, जिन पर




वीडियो पोस्ट करने, उसे वायरल करने और मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना में शामिल होने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि वीडियो को जानबूझकर भड़काऊ तरीके से फैलाया गया, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। धनुषा की घटना के विरोध में सीमावर्ती शहर बीरगंज में भी हालात तेजी से बिगड़े। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो कुछ ही देर में हिंसक रूप ले बैठा। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों को जाम कर टायर जलाए और नारेबाजी की। हालात तब और गंभीर हो गए, जब भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान एक स्थानीय पुलिस थाने में भी तोड़फोड़ की गई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया।

स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को आंसू गैस के लगभग आधा दर्जन गोले छोड़ने पड़े। काफी मशक्कत के बाद सुरक्षाबलों ने भीड़ को तितर-बितर किया और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। झड़पों में कम से कम सात पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हुए हैं। हालांकि, किसी भी नागरिक के गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

पुलिस कार्रवाई और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के बाद बीरगंज में हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे, लेकिन प्रशासन अब भी पूरी तरह सतर्क है। सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे से दोबारा तनाव न फैले। पर्सा जिले के मुख्य जिला अधिकारी भोला दहाल ने सार्वजनिक अपील जारी करते हुए लोगों से शांति और संयम बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नेपाल एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज है, जहां आपसी सौहार्द सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी तरह की अफवाह, भ्रामक सूचना या नफरत फैलाने वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने सोशल मीडिया को लेकर सख्त चेतावनी दी है। जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अफवाह फैलाने, भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने या धार्मिक-सामाजिक

**(जीएनएस)।** वैमनस्य बढ़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइबर निगरानी तेज कर दी गई है और संदिग्ध अकाउंट्स पर नजर रखी जा रही है।

धनुषा पुलिस के प्रवक्ता गणेश बाम ने बताया कि हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह जांच की जा रही है कि वीडियो किसने बनाया, किस उद्देश्य से उसे वायरल किया गया और इसके पीछे किसी संगठित साजिश की भूमिका है या नहीं। पुलिस का दावा है कि दोषियों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलाई जाएगी।

भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में हुई यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि सोशल मीडिया किस तरह चंद मिनटों में शांति भंग कर सकता है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैलने वाली भड़काऊ सामग्री को समय रहते रोका जाए। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि शांति बनाए रखने के लिए सतर्कता और जिम्मेदारी दोनों बेहद जरूरी हैं।

## इंडिगो तकनीकी व्यवधान: DGCA को सौंपी जांच रिपोर्ट, अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस में हाल ही में सामने आए तकनीकी व्यवधान के मामले को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गंभीर कदम उठाते हुए विशेष जांच समिति गठित की थी, जिसने इस घटना की विस्तृत छानबीन की। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को सौंप दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि रिपोर्ट के सभी बिंदुओं की गंभीरता से समीक्षा की जा रही है और जरूरत पड़ने पर एयरलाइंस से अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे जा सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूरी जांच प्रक्रिया पूरी होने और सभी तथ्यों की पुष्टि होने के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई या दंडात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया जाएगा, ताकि निर्णय पूरी तरह न्यायसंगत और सुरक्षित हो।

मंत्री ने कहा कि विमानन क्षेत्र से जुड़े नियम हमेशा यात्रियों और विमानों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानकर बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि खासकर पावर बैंक और लिथियम बैटरी जैसी संवेदनशील वस्तुओं को लेकर DGCA कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करता। इसके लिए तकनीकी अध्ययन, गहन शोध और विशेषज्ञों की राय ली जाती है ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। उन्होंने कहा कि DGCA के नियम अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। किसी भी नियम को लागू करने से पहले अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाता है, और नियम लागू होने के बाद उसका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाता है।

DGCA ने दिसंबर 2025 से लिथियम बैटरी और पावर बैंक की सुरक्षा को लेकर एक नई एडवाइजरी भी जारी की है। इसके तहत एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वे विमान में पावर बैंक और लिथियम बैटरी के परिवहन से पहले विस्तृत सेफ्टी रिस्क असेसमेंट करें। यात्रियों को ऑनबोर्ड अनाउंसमेंट और अन्य माध्यमों से लिथियम बैटरी की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि वे किसी भी अनहोनी की स्थिति में तत्काल सावधानी बरत सकें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि केबिन बैगेज में पावर बैंक और स्पेयर बैटरी की कड़ी निगरानी की जाए और किसी भी डिवाइस में ओवरहीटिंग या धुआं दिखने पर यात्रियों को तुरंत केबिन क्रू को सूचित करने की सलाह दी जाए। साथ ही, केबिन क्रू की ट्रेनिंग की समीक्षा की जाएगी और उन्हें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राम मोहन नायडू ने कहा कि एयरलाइंस और DGCA की जिम्मेदारी है कि वे तकनीकी व्यवधानों और संभावित जोखिमों को गंभीरता से लें। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद एयरलाइंस ने अपने तकनीकी स्टाफ और ऑपरेशन टीमों के साथ बैठक कर विमानन सुरक्षा मानकों की समीक्षा की है। मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद यात्रियों और एयरलाइंस दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि DGCA की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसी भी तरह का बदलाव, सुधार या दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि सभी तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की पूरी तरह जांच हो सके।

केंद्रीय मंत्री ने अंत में कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र में सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों की अनदेखी देश और यात्रियों के लिए गंभीर खतरा हो सकती है।

## ज्ञान, संस्कृति और प्रतिभाओं का संगम है बनारस: नरेंद्र मोदी

**(जीएनएस)।** वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर देशभर से आए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी केवल आध्यात्म और संस्कृति का ही नहीं, बल्कि ज्ञान, खेल और प्रतिभाओं का भी संगम रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत की विकास यात्रा की सराहना पूरी दुनिया कर रही है और इसका सकारात्मक प्रभाव खेल जगत में भी साफ दिखाई दे रहा है। डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम से जुड़े इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह में देश के 28 राज्यों से आई 58 टीमों के एक हजार से अधिक खिलाड़ी और कोच शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने मेजबान सांसद के रूप में सभी खिलाड़ियों और अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन न केवल खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मंच देते हैं, बल्कि शहर और राज्य की पहचान



को भी नई ऊंचाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत 'नमः पार्वती पतये हर-हर महादेव' के उद्घोष के साथ की और कहा कि काशी की आत्मा में परंपरा भी है और प्रगति भी। उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल केवल शारीरिक ताकत का खेल नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, संतुलन, आपसी तालमेल और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस खेल में हर खिलाड़ी 'टीम फर्स्ट' की भावना के साथ खेलता है और यही भावना आज भारत की प्रगति का भी आधार बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे एक टीम विश्वास, समन्वय और तत्परता के बल पर जीत हासिल करती है, उसी तरह देश भी सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल भुगतान की सफलता हो, 'एक पेड़ मां के नाम' जैसा पर्यावरणीय संकल्प हो या फिर विकसित भारत का लक्ष्य—हर क्षेत्र में देशवासियों की भागीदारी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे खेल के मैदान में भी इसी भावना को आत्मसात करें और देश का नाम रोशन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत के खेल परिदृश्य में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सरकार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण, चयन प्रक्रिया और खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025 जैसे सुधारों से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। इससे युवा खिलाड़ी शिक्षा और खेल दोनों में संतुलन बनाते हुए आत्मनिर्भर बन सकेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी को काशी के खेल मानचित्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। होटल, परिवहन, पर्यटन और छोटे व्यवसायों को इससे सीधा लाभ मिलता है।

इससे पहले जी-20 बैठकों, सांस्कृतिक उत्सवों और प्रवासी भारतीय सम्मेलनों जैसे बड़े आयोजनों ने भी वाराणसी को वैश्विक पहचान दिलाई है। उन्होंने काशी की खेल परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह शहर सदियों से ज्ञान, संस्कृति और खेल प्रतिभाओं का केंद्र रहा है। बीएचयू, यूपी कॉलेज और काशी विद्यापीठ जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से निकले खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। कुश्ती, मुक्केबाजी, नौकायन, कबड्डी और अन्य पारंपरिक खेल काशी की पहचान का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और आज वॉलीबॉल जैसे आधुनिक खेल इस विरासत को और समृद्ध कर रहे हैं।

## उत्तर भारत में ठंड का कहर, घना कोहरा बना आफत, अगले 5 दिनों में और बिगड़ेगा मौसम, IMD का अलर्ट जारी

**(जीएनएस)।** नई दिल्ली। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों में रविवार से ठिठुरन बढ़ गई है और सुबह के समय घनी धुंध ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, जबकि रेल और हवाई यातायात पर भी इसका व्यापक असर पड़ा। दिल्ली में रविवार को उड़ानों की आवाजाही सबसे ज्यादा प्रभावित रही और लगभग दो-तिहाई फ्लाइट्स अपने तय समय से देरी से रवाना हुईं।

घने कोहरे के कारण सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जिससे हाईवे, एक्सप्रेसवे और शहर की मुख्य सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में कोहरे का असर लगातार बना हुआ है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर ने ठंड को और तीखा कर दिया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने 5 से 7 जनवरी के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है, जो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का संकेत देता है। आईएमडी का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ठंड और अधिक तीव्र हो सकती है, खासकर सुबह और रात के समय। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा।

रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक रहा, लेकिन ठंडी हवाओं और कोहरे के कारण ठंड ज्यादा महसूस की गई। अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आयानगर में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह के समय राजधानी के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ।

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले सात दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है। खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में इसका असर ज्यादा रहेगा। 5 से 8 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में दिन का तापमान ठंडा रहने की संभावना है, जिससे लोगों को दिन में भी ठिठुरन का अहसास होगा।

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। कई स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे चला गया है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात का तापमान शून्य के आसपास पहुंच गया है, जिससे पाला पड़ने की आशंका बढ़ गई है।

उत्तर प्रदेश में भी ठंड और शीतलहर का असर साफ नजर आ रहा है। शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से ऊपर रहा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।